

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 16 फरवरी, 2009

विषय: हरिद्वार में पुराना दिल्ली-नीति पास मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य (ज्वालापुर-हरि की पैड़ी-भौपतवाला) हेतु प्रशासकीय, वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 640/कु.मे./लो.नि.वि. दिनांक 04.11.2008 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन रु. 1892लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु. 1875.53लाख (रु. अठारह करोड़ पच्चाहत्तर लाख तिरपन हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति देते हुए, वित्तीय वर्ष 2008-09 में रु. 500लाख (रु. पांच करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -

1. उक्त स्वीकृति व्यय वित्त समिति की दिनांक 03.02.2009 को आयोजित बैठक में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है। अतएव कार्य कराते समय, सचिव, नियोजन/ सदस्य सचिव, व्यय वित्त समिति, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1382/ई.एफ.सी./नियो. /2008-09 दिनांक 09.02.2009 में उल्लिखित व्यय वित्त समिति के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दो बराबर किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही दूसरी किश्त का कोषागार से आहरण किया जाएगा।
3. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए। मार्ग बनने के बाद इसके गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 'थर्ड पार्टी चैकिंग' की व्यवस्था भी की जाएगी और मार्ग के कार्यों की उक्त तृतीय पक्ष से चैकिंग की रिपोर्ट शासन को भी समय-2 पर दी जाएगी। उक्त पर होने वाला व्यय उक्त अनुमोदित लागत से ही वहन किया जाएगा।
4. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गई है।
6. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।
7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन कड़ाई से किया जाए।
9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री का ही प्रयोग में लाया जाए।
10. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्यस्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिए गये निर्देशों के अनुसार कार्य कराया जाए।
11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाएगी।
12. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

13. सड़क निर्माण के पश्चात यह सुनिश्चित किया जाए कि फुटपाथ पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो तथा अतिक्रमण हटाने के संबंध में जहां आवश्यक हो, वहां जिला प्रशासन का सहयोग प्राप्त किया जाए।
 14. कुम्भ मेला अन्तर्गत कार्यों का सम्पादन शीघ्रातिशीघ्र कराते हुए आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार को यथाशीघ्र प्रेषित किया जाए।
 15. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2009 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा और उक्त विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जाएगी।
 16. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि इस पर अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके, उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जाएगा।
 17. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाए।
 18. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा।
 19. कार्य की गुणवत्ता/समयबद्धता हेतु मेलाधिकारी एवं संबंधित निर्माण एजेंन्सी पूर्णतया उत्तरादायी माने जाएंगे।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के 'अनुदान संख्या-13' के 'आयोजनागत' पक्ष के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-80-सामान्य-आयोजनागत -800-अन्य-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-07-हरिद्वार कुम्भ मेला, 2010 हेतु अवस्थापना सुविधा" के अन्तर्गत मानक मद "20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे डाला जाएगा।"
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं. 1198/XXVII(2)/2009 दिनांक 12फरवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

संख्या : 287 (1)/IV(1)/200 तददिनांक 16.02.09

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, नियोजन/सदस्य सचिव, व्यय वित्त समिति, उत्तराखण्ड शासन को उनके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 09.02.2009 के क्रम में एवं नियमानुसार 'थर्ड पार्टी चैकिंग' की व्यवस्था किए जाने हेतु।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
10. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
12. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनुसचिव।